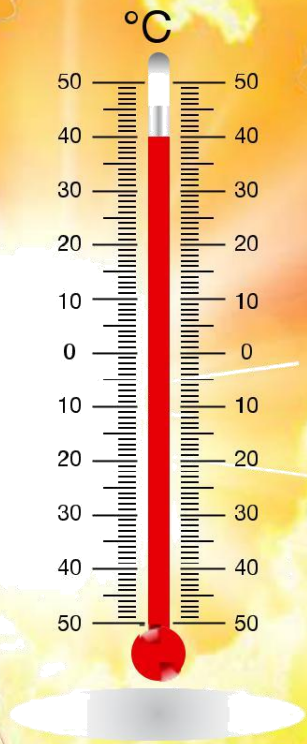




आपदा संवाद



2

खबरों में



6

सीबीआरएन आपातस्थितियों
के प्रति तैयारी



8

लू की आपदा पर
डॉ० एन.एम. राठी
से बातचीत



आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर प्रथम भारत-जापान कार्यशाला आयोजित की गई

भारत और जापान जो संसार के दो सर्वाधिक आपदा प्रवण देश हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर), खासतौर पर भूकंप, से संबंधित मुद्दों; पर चर्चा करने के लिए 19-20 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में एक दो-दिवसीय कार्यशाला के लिए एक साथ इकट्ठा हुए।

जापान अग्नि के प्रशांत घेरे (पेसेफिक रिंग ऑफ फायर) के साथ स्थित है और भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देश है। जापान के तबाही लाने वाले भूकंपों के लंबे इतिहास को देखते हुए, सामुदायिक जागरूकता का इस देश में एक बहुत उच्च स्तर है। इसकी प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी, विशेष रूप से भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में संसार की सर्वाधिक उन्नत जानकारीयों में से एक है।

भारत का तेजी से शहरीकरण हो रहा है और बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश तुरंत आवश्यक है। चूंकि, भारत के भू-भाग का तकरीबन 59 % भाग सामान्य से लेकर भयंकर भूकंपों के प्रति प्रवण है, इसलिए ऐसा करने से न केवल किसी भूकंप की घटना में जानों को बचाया जाएगा बल्कि इसका एक बड़ा आर्थिक अर्थ भी होगा कि यह निवेश भूकंप से निपटने में देश को सक्षम बनाने के लिए किया गया है।

इस कार्यशाला ने यह पता लगाने में मदद की कि जापान ने किस प्रकार अपने बुनियादी ढांचे को वर्तमान तथा आगामी आपदा जोखिमों के प्रति समुत्थानशील बनाने के लिए निवेश किया है। कार्यशाला से भूकंप का पता लगाने तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों के क्षेत्र में हुई हालिया प्रगति की बातों को समझने और उन्हें भारत के संदर्भ में अनुकूल बनाने में भी मदद मिली।

कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से भारत के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा जापान सरकार के द्वारा किया गया। डॉ० राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

कार्यशाला के दौरान छह तकनीकी सत्रों – आपदा प्रबंधन नीति रूपरेखा, जोखिम आंकलन, आपदा समुत्थानशील बुनियादी ढांचा, पूर्व चेतावनी प्रणाली, उप-राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी/मोचन और निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण (अप्रोच)–का आयोजन किया गया।

दोनों देशों की सरकारों से लगभग 120 प्रतिनिधियों शिष्टमंडलों, शिक्षण संस्थाओं, विशिष्ट आपदा प्रबंधन एजेंसियों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी संगठनों में कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला पर एक विस्तृत लेख को आपदा संवाद के अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा।

एनडीएमए ने राज्यों से आपातकालीन सीटी का उपयोग करने का आग्रह किया है

किसी संकट की स्थिति में एक आपातकालीन सीटी एक जीवन-रक्षक अस्त्र है। किसी भूकंप के बाद, किसी पीड़ित की आवाज इतनी ताकतवर नहीं होगी है कि वह बचाव-कर्ताओं तक पहुंच जाए अतः सीटी बचाव-कर्ताओं को यह बता सकती है कि कोई मलबे के नीचे फँसा हुआ है। यह दोतरफा संचार प्रणाली के रूप में काम कर सकती है। बचाने वाले लोग भी मलबे के निकट अपनी उपस्थिति की सूचना देने के लिए इस सीटी को बजा सकता हैं। कम पिच वाली इसकी तेज आवाज को पहचानना आसान है और अफरातफरी/अराजकता की स्थिति में यह अच्छी तरह काम करती है।



एनडीएमए ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों से उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सभी प्रतिनिधियों/भागीदारों को सम्मेलन/कार्यशाला की किट में आपातकालीन सीटी को शामिल करने का आग्रह किया गया है। अनेक अन्य देश भी इस प्रथा को अपना रहे हैं।

सीबीआरएन आपातस्थितियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनडीएमए ने 5-10 मार्च, 2018 से मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर एक छह दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने सीबीआरएन आपातस्थितियों से निपटने के लिए हवाई अड्डा आपातस्थिति प्रबंधकों की तैयारी को और बेहतर बनाया।

सीबीआरएन आपातस्थितियों का संबंध रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय, नाभिकीय सामग्री के कारण उत्पन्न होने वाले खतरों से है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और नाभिकीय औषधीय एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इनमास) के सहयोग से किया गया।

इस कार्यक्रम में वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग सहित जांच तथा विसंदूषण का सजीव प्रदर्शन के साथ व्याख्यान (लेक्चर) तथा क्षेत्र प्रशिक्षण शामिल थे। सीबीआरएन आपातस्थितियों से निपटने के लिए आईएच से लैस करने के अलावा, इस कार्यक्रम ने भागीदारों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता और प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता भी उपलब्ध कराने में समर्थ बनाया।

कुल 200 कार्मिकों को सीबीआरएन आपातस्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इनमें एक आधा दिन के मॉड्यूल में 150 कामकाजी स्तर के स्टाफ का सूग्राहीरण शामिल था। इससे पहले भी, इसी तरह के कार्यक्रमों को चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डे पर सफलता से आयोजित किया गया।

एनडीएमएस प्रायोगिक परियोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम



एनडीएमएस ने 8-9 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सेवा (एनडीएमएस) से जुड़े उपस्करों को इस्तेमाल करने के लिए राज्य/जिला कार्मिकों को उनके बारे में जानकारी देने तथा समर्थ बनाने के लिए एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया है। राज्य/जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्रों (एसईओसी/डीईओसी) में कार्य अनुभव वाले मध्यम-स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों को उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया जैसे वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (वी-सेट), वायस कॉल, इंटरनेट, ई-मेल, वीडियो, सेटलाइट फोन और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो के साथ अन्य उपकरण।

एनडीएमएस गृह मंत्रालय, एनडीएमएस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 81 खतरा-प्रवण जिलों के मुख्यालयों के नियंत्रण कक्षों को जोड़ने की एक प्रायोगिक परियोजना है। इसका उद्देश्य किसी आपदा की स्थिति में ईओसी के लिए बाधा-रहित संचार आधार ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करना है।

हिमाचल प्रदेश में भूकंप का कृत्रिम अभ्यास

हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ सहयोग से एनडीएमएस ने 9 फरवरी, 2018 को भूकंप से निपटने की तैयारी पर एक राज्य स्तरीय कृत्रिम अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास जिसका आयोजन राज्य के सभी जिलों में एक साथ किया गया, का उद्देश्य सभी हितधारकों को, अपनी आपदा मोचन योजना की कारगरता का मूल्यांकन करने के लिए समर्थ बनाना था।



यह कृत्रिम अभ्यास एक तीन-दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा था जो 7 फरवरी, 2018 को एक समन्वय सम्मेलन के साथ शुरू हुआ जिसके बाद 8 फरवरी, 2018 को एक टेबल-टॉप अभ्यास आयोजित किया गया।

पूरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र 4 तथा 5 में पड़ता है, और इस राज्य में भूकंपों के दर्ज इतिहास के अनुसार रिक्टर स्केल 4 या उससे अधिक की क्षमता वाले भूकंपों के कारण 80 बार राज्य की धरती हिल चुकी है। 1905 के कांगड़ा भूकंप जिसमें कम-से-कम 20 हजार लोग मारे गए, राज्य द्वारा झेला गया अंतिम बड़ा भूकंप रहा है। तब से अब तक राज्य में जनसंख्या विस्फोट तथा निर्माण गतिविधि के चलते भूकंप का खतरा कई गुना बढ़ गया है।

मणिपुर में आईआरएस प्रशिक्षण

एनडीएमएस ने 23-24 फरवरी, 2018 को इंफॉल, मणिपुर ने घटना मोचन प्रणाली (आईआरएस) में एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया।

आईआरएस किसी घटना के व्यवस्थित मोचन का एक कारगर तंत्र है। हर हितधारक को भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां सौंप कर यह एक अति जटिल मोचन प्रक्रम को विखंडित करता है जिसमें कारण एक तीव्र तथा सुचारु मोचन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

इसे भारत में किसी आपदा के आकार, स्थान, किस्म तथा जटिलता के निरपेक्ष सफलता-पूर्वक लागू किया जा सकता है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी हितधारक विभागों के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। •



घातक ग्रीष्म लहर (लू) : कार्य योजना-2018



भारत का एक बड़ा भाग हर साल लू से जंग लड़ता है। अप्रैल और जून के बीच लू की अवधि के दौरान कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और उससे ऊपर चला जाता है।

लू के कारण होने वाली मौतों के बारे में रिपोर्टें हर साल सुर्खियां बनती हैं। तथापि, सटीक आंकड़ों के अभाव में अलग-अलग रिपोर्टों में मौतों की संख्या में भिन्नता देखी जाती है।

सामान्यतः सीधे लू की चपेट में आने, जिसमें पीड़ित व्यक्ति कुछ घंटों के अंदर मर जाता है, के कारण हुई मौतों वाले अधिक स्पष्ट मामलों की लू की वजह से हुई मौतों के रूप में रिपोर्ट की जाती है। दूसरा सामान्य रूप अप्रत्यक्ष लू का लगना है जिसमें मुख्यतः बुजुर्ग या पुराने रोगों के पीड़ित लोग शिकार बनते हैं। डॉ० दिलीप मावलंकर, निदेशक, भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान, गांधी नगर के अनुसार “लू लगने के 24-48 घंटों के अंदर मौत हो जाती है और इन्हें अज्ञानता के कारण लू की वजह से हुई मौत नहीं माना जाता”।

2015 में, लू से होने वाली मौतों की संख्या 2000 से अधिक थी। इसके अलावा, यह संख्या अन्य किसी आपदा द्वारा हुई मौतों की संख्या की तुलना में अधिक थी। घातक ग्रीष्म लहर की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2016 में “लू की रोकथाम तथा प्रबंधन-कार्य योजना बनाने हेतु दिशानिर्देश” को सूत्रबद्ध किया और सभी राज्यों में परिचालित किया। यह दिशानिर्देश प्रचंड लू के प्रतिकूल प्रभागों को कम करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन, समन्वय और मूल्यांकन के लिए यह दिशानिर्देश एक रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं। इसको कारगर ढंग से लागू करने से वर्ष 2016 तथा 2017 में लू से होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

लू असामान्य रूप से उच्च तापमान जो सामान्य अधिकतम तापमान से ज्यादा होता है, की एक अवधि होती है जो मॉनसून से पहले (अप्रैल से जून) के गरमी के मौसम के दौरान होती है। प्रचंड तापमान तथा उसके कारण होने वाले वातावरण की स्थितियों के कारण संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि लू के कारण शरीर में पानी की कमी (डीहाइड्रेशन), गरमी से शरीर का बेहाल होना, शरीर की अकड़न और कभी-कभी लोगों की मौत की हो जाती है।

श्री आर.के. जैन, सदस्य, एनडीएमए कहते हैं “हमने राज्यों द्वारा की गए तैयारी तथा उनके द्वारा उठाए गए कदमों की बारीकी से समीक्षा और मॉनिटरिंग की और सभी हितधारकों के मिले-जुले प्रयासों से हम लू के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भारी कमी लाने में समर्थ हुए” और उन्होंने यह भी कहा कि हमारा इरादा इस साल लू से एक भी व्यक्ति की जान न जाने देने का है अर्थात्, इस आपदा के प्रति हमारा दृष्टिकोण जीरो टॉलरेंस वाला है।



ग्रीष्म लहर 2018 से निपटने के लिए, एनडीएमए ने आंध्र प्रदेश की सरकार के सहयोग से विजयवाड़ा में 21-22 फरवरी, 2018 को सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुभव को बांटने हेतु लू के खतरे में कमी लाने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में लू संबंधित कार्य योजनाओं को तैयार और लागू करने में, जन-जागरुकता अभियान, सामुदायिक क्षमता निर्माण तथा देसी परंपरा तथा ज्ञान के पुनर्जीवन के महत्त्व पर प्रकाश डाला। कार्यशाला में सटीक जानकारी तथा आंकड़े इकट्ठा करने और सर्वाधिक उपयुक्त प्रशमन उपायों की जरूरत पर भी चर्चा हुई।

लेपिट जनरल एन.सी. मारवाह (सेवानिवृत्त) तथा की कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए भी कार्यशाला में उपस्थित हुए।

एनडीएमए ने वर्ष, 2017 में इसी प्रकार की एक कार्यशाला का आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में किया था।



कुछ संवेदनशील राज्यों, जो सफलता के साथ लू से लड़ने में काफी हद तक समर्थ रहे हैं, द्वारा बेहतर प्रथाओं के सांझा किए जाने से कार्यशाला में राज्यों को लू की योजनाओं को अपडेट करने में सहायता मिली।

लू के असर के प्रशमन का एक सबसे प्रभावी तरीका, संवेदनशील आबादियों को स्थानीय भाषाओं में जागरुकता अभियान के माध्यम से उनकी सामुदायिक क्षमता निर्मित करके अपनी मदद स्वयं करने के लिए तैयार करना है। इससे संवेदनशील आबादियां लू की स्थिति पहचानने और उसके प्रति मोचन के लिए समर्थ हो जाती है। समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले प्याऊ और सराय (वाटर किऑस्क एंड शेल्टर) से इलाके में हर आने-जाने वाले व्यक्ति को गरमी के महीनों के दौरान खुद को ठंडा रखने में मदद मिलती है और ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की दिशा में समुदाय की भागीदारी के उत्तम उदाहरण हैं।

प्राधिकरण/प्राधिकारी मदद करेंगे किंतु सबसे अच्छा तरीका अपने आपकी, अपने परिवार तथा अपने मित्रों की मदद करना है। क्यों न आप ऐसे शुरूआत करें कि आप उन पक्षियों जो गरम तथा उमस भरे मौसम के दौरान आपकी बालकनी या टैरेस पर किसी जगह आकर रुकते हैं, के लिए पीने के साफ पानी से भरा एक प्याला रख दें ? •

तकनीकी सत्र

- i) लू कार्य योजना और जोखिम न्यूनीकरण
- ii) लू की पूर्व चेतावनी, पूर्वानुमान तथा तैयारी
- iii) अनुभव साझा करना और 2018 में लू प्रशमन उपायों के लिए सीखे गए सबक तथा उभरते मुद्दे
- iv) लू के प्रति क्षमता निर्माण और प्रभावी मोचन को और बेहतर बनाना
- v) लू कार्य योजना की मॉनिटरिंग, समीक्षा तथा अपडेट करने का कार्य



जामनगर को सीबीआरएन

आपातस्थिति के लिए तैयार करना

तीव्र औद्योगिकीकरण और प्रौद्योगिकीय प्रगतियों के साथ सीबीआरएन आपातस्थितियां जो रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय सामग्री के कारण होने वाले खतरों से संबंधित हैं, पूरे संसार में एक वास्तविकता बन गई हैं। ये मानवीय भूलों, दुर्घटनावश एक्सपोजर, आतंकवादी हमलों और तोड़-फोड़ के कारण हो सकती हैं, साथ ही ये किसी भूकंप, चक्रवात आदि के बाद एक दूसरे दर्जे की आपदा (सेकेंडरी डिजास्टर) के रूप में मानी जा रही है।

सीबीआरएन आपातस्थितियों से निपटने के लिए विशेष दक्षताओं तथा प्रयासों और सभी हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। एक छोटी सीबीआरएन संबंधित घटना से भी लोगों में डर फैल सकता है।

सीबीआरएन आपदाएं यद्यपि, कुछ गिनी-चुनी होती हैं, किंतु ये जान तथा माल, दोनों को तुरंत बड़ी मात्रा में हानि पहुंचाने के साथ-साथ दीर्घावधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। अतः संवेदनशील प्रतिष्ठानों की इनसे निपटने की तैयारी और जूझने की क्षमता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

इन आपदाओं से होने वाली हानियों को स्थानीय संसाधनों की, ऐसी स्थितियों में तेजी तथा कारगर ढंग से कार्रवाई करने के लिए, क्षमता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। नियमित कृत्रिम अभ्यासों का आयोजन करना हितधारकों के बीच समन्वय तथा तालमेल हासिल करने का एक कारगर तरीका है। एनडीएमए नियमित रूप से सीबीआरएन आपदाओं के लिए तैयारी तथा मोचन प्रक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों के अंतर्गत ऐसे कृत्रिम अभ्यासों का संचालन करता है। इस साल जनवरी में, गुजरात एनडीएमए के अनुरोध पर एनडीएमए ने जामनगर, गुजरात को कृत्रिम अभ्यास के संचालन के लिए चुना।

जामनगर उच्च जोखिम भूकंपीय क्षेत्र-IV में पड़ता है। इसमें अनेक बड़ी दुर्घटना के खतरों (एमएएच) वाली यूनिटें हैं जैसे रिलायंस पेट्रो केमिकल, एसआर रिफाइनरी, टाटा केमिकल्स, गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन (जीएसएफसी) आदि। कुणाल शर्मा, परामर्शदाता, रासायनिक तैयारी, एनडीएमए ने कहा "जिले की असुरक्षितता/संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि खतरनाक रासायनिकों की भारी मात्राओं को न केवल इन संयंत्रों में स्टोर किया जाता है बल्कि इन्हें घाट (जेटी) से रिफाइनरियों तथा विलोमतः लाया ले-जाया भी जाता है, और एक हल्के भूकंप से भी भारी नुकसान तथा तबाही हो सकती है।"

जामनगर की समुद्र तटीय अवस्थिति को देखते हुए चक्रवात तथा सुनामी के खतरे को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यह जिला पाकिस्तान के कुछ एयर बेसों से बस लगभग 20 मिनट के उड़ान-समय (फ्लाईंग टाइम) की दूरी पर हैं।

यह अभ्यास 3 जनवरी को एक समन्वय सम्मेलन के साथ शुरू हुआ जिसमें इसमें भाग लेने वालों को घटना मोचन प्रणाली की अवधारणा को तथा उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को समझने की मदद की। इसके बाद सीबीआरएन आपातस्थितियों और उससे जुड़े उपकरणों के निपटान/प्रबंधन पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) द्वारा प्रथम मोचकों के एक तीन-दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 18 जनवरी को टेबल-टॉप अभ्यास में, विभिन्न आपदा परिदृश्यों पर चर्चा की गई और अगले दिन वास्तविक अभ्यास में उपयोग करने के लिए भागीदारों से उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी गईं।

कृत्रिम अभ्यास के दौरान जिला प्रशासन की आपातकालीन मोचन प्रशासन के साथ-साथ उद्योग की आपातकालीन मोचन योजनाओं की कारगरता की जांच के लिए अनेक परिदृश्यों की रचना की गई। आंतकवादियों द्वारा एक क्लोरीन टैंकर का अपहरण किया गया, रिलायंस रिफाइनरी के मुख्य द्वार से इसको टकराया गया और विस्फोट कराया गया। आंतकवादियों के एक दूसरे समूह ने एलपीजी वाले ईंधन से विस्फोट किया जिससे रिफाइनरी में आंग लग गई। इसके साथ ही जीएसएफसी की एक अमोनिया फाइपलाइन में रिलायंस टैंक फॉर्म के मुख्य द्वार के बाहर तोड़-फोड़ की गई। लगभग 20 मिनटों के बाद, पास के सिक्का गांव से दो बड़े धमाकों की रिपोर्ट की गई। इसके साथ ही गांव से होकर जाने वाली अमोनिया फाइपलाइन में भी तोड़-फोड़ की गई।

परिस्थितियों की मांग थी कि रिफाइनरी के साथ-साथ प्रभावित गांव में ऑन-साइट तथा ऑफ-साइट, दोनों मोचन संबंधित प्रक्रियाएं की जाएं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, गाड़ी द्वारा राहत शिविर तक ले जाना था और चिकित्सा सहायता दी जानी थी। जिला प्रशासन ने अपने ईओसी ओ सक्रिय किया, संसाधनों को इकट्ठा किया और एक सुरक्षित योजना शुरू की। एनडीएमए के मेजर जनरल वी.के. दत्ता (सेवानिवृत्त), जिन्होंने संपूर्ण अभ्यास का नेतृत्व किया, ने इस मौके पर कहा "इसके लिए विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के साथ-साथ जिला प्रशासन, केंद्रीय एजेंसियों और उद्योग के बीच समन्वय जरूरी था, इसलिए परस्पर सहायता-योजनाओं को सक्रिय किया गया और सभी हितधारकों ने पर्याप्त रूप से इस परिस्थिति में मोचन कार्य किया है।"



बाद में एक विस्तृत समीक्षा (डीब्रीफिंग) को किया गया, खामियों की पहचान की गई और उनको सुधारने के लिए उपायों पर चर्चा की गई।

श्री रवि शंकर, जिला कलक्टर, जामनगर ने कहा, "इस अभ्यास से हमें आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए हमारी क्षमताओं को समझने तथा सभी हितधारकों के प्रशिक्षण में मदद मिली है। इसने संवदेशनशील समुदायों को जोखिमों पर जानकारी के साथ-साथ किसी आपदा के असर को कम करने के उपायों के प्रति जागरूक बनाने में मदद मिली। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभ्यास ने लोगों की आंखें खोल देने वाले एक कार्यक्रम के रूप में भी काम किया, हमें खामियों को दूर करने और संशोधन कार्य में मदद दी, हमारे जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र (डीईओसी) और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अपग्रेड करने और सुचारु बनाने में मदद की।

जिला प्रशासन अब प्रायः हर महीने एक या दो आपदाओं पर एक कृत्रिम अभ्यास संचालित करता है। उन्होंने कहा 'हम इन अभ्यासों में जिले में मौजूद उद्योगों, स्थानीय लोगों, केंद्रीय एजेंसियों को शामिल करते हैं ताकि हम अभ्यास के साथ इन आपदाओं के प्रति हमारे मोचन कार्य चुस्त-दुरुस्त बने रहें। •



डॉ० एन.एम. राठी से ग्रीष्म लहर (लू) पर बातचीत



लू एक शांत किस्म की आपदा है। यह धीरे-धीरे वातावरण में पहुंचती है, एक लंबी अवधि तक बनी रहती है और अपने शिकार की चुपचाप जान ले लेती है। इन घातक लेहरों के लिए इनके वातावरण में पहुंचने से काफी पहले इनसे निपटने की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनके बारे में ओर जानकारी के लिए, आपदा संवाद ने डॉ० एन.एम. राठी, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नागपुर नगर निगम से बातचीत की। डॉ० राठी नागपुर लू कार्य योजना तैयार करने के काम में सहायक रहे थे।

प्रश्न : लू घातक सिद्ध हो सकती है। लू-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इसके प्रतिकूल असर को कम करने के लिए क्या तैयारियाँ करते हैं ?

उत्तर : लू का मौसम जो मार्च के आधे महीने बाद शुरू होता है और जून तक बना रहता है और कभी-कभी कुछ मामलों में जुलाई तक बढ़ जाता है, के दौरान उन्हें दैनिक तापमान के पूर्वानुमान पर निगाह रखनी चाहिए। यदि अधिकतम तापमान के 43 डिग्री या उससे अधिक रहने का पूर्वानुमान हो तो लोगों को दोपहर के 12 और 04 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचा रहना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो हर आधे घंटे बाद पर्याप्त मात्रा में पानी अर्थात् पूरा एक गिलास पानी पीना चाहिए। ढीले, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने से भी लू से बचने में मदद मिलती है।

प्रश्न : जनसंख्या के सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग कौन से हैं ? लू से जनको बचाने के लिए उनकी मदद करने हेतु क्या विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए ?

उत्तर : जो लोग घर से बाहर रहकर काम करते हैं या भारी शारीरिक गतिविधि वाले जैसे निर्माण में लगे कामगार, विक्रेता, कुली, ईंट-भट्टा पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ढाबे पर काम करने वाले/रसाइये, झुग्गी बासियों आदि सर्वाधिक संवेदनशील वर्ग में आते हैं। उन्हें तेज लू वाले घंटों के दौरान काम करने से बचना चाहिए क्योंकि सूरज की तेज रोशनी में लंबे समय तक रहने से गरमी से थकावट होना, ताप आघात (लेज लू लगना) आदि हो सकता है। लोगों को हम समय अपने साथ पानी की एक बोतल रखनी चाहिए, अपने सर को ढक कर रखना चाहिए और चप्पल जूते आदि पहने रखने चाहिए। उन्हें काम के दौरान बार-बार छोटे-छोटे समय विराम (ब्रेक) लेना चाहिए।

बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी अन्यो की तुलना में अधिक असुरक्षित/संवेदनशील होते हैं। अतः यह जरूरी है कि प्रचंड लू के मौसम के दौरान, जितना संभव हो बार-बार उनकी देखभाल करते रहना चाहिए।

प्रश्न : लू प्रवण क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सरल, किफाईती तकनीकों के बारे में हमें बताएं ?

उत्तर : कुछ बहुत सरल तकनीकों जैसे छतों पर कृषीय अपशिष्ट रखना, एक टैरेस गार्डन तैयार करना या छत और दीवारों पर एक घास वाला छप्पर (ग्रीन नेट) फैला देने से घर के अंदर के तापमान में भारी कमी लाई जा सकती है। चूने की कोटिंग और छत पर छोटा सा तालाब बनाने के देसी तरीके से भी तापमान को कम रखने में मदद मिलती है। बैरियर कवर जो ऊष्मा को सोखने की बजाय बाहर को फेंकते हैं, भी तापमान कम करने में मदद करते हैं। छत पर बगीचा, खड़े दीवार-बगीचे (वर्टिकल वॉल गार्डन) और दीवारों पर पौधों से भी तापमान के कारण गर्मी में कमी आती है।

प्रश्न : क्या लू का सटीक पूर्वानुमान लगाना संभव है ? समुदायों तक इस पूर्व चेतावनी को कैसे पहुंचाया जा सकता है ?

उत्तर : हां, लू का पूर्वानुमान लगाना संभव है। भारत मौसम विज्ञान विभाग कई दिन पहले से ग्रीष्म लहरों के बारे में पूर्वानुमान करता है। इससे प्राधिकरणों को समुदायों को तैयार करने तथा सावधान करने का काफी समय मिल जाता है। चेतावनियों को ई-मेल, एसएमएस, वॉट्सएप ग्रुपों के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

किसी आसन्न लू के बारे में समुदायों को सतर्क करने के लिए मीडिया का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। सहायता समूहों और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता जैसे सहायक नर्स/दाई (एएनएम), मान्यता प्राप्त समाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला आरोग्य समिति के माध्यम से अंतर व्यक्तिगत बातचीत करना, लू और इसके प्रतिकूल प्रभावों तथा इससे निपटने के उपायों के बारे में सूचना पहुंचाने का एक कारगर तरीका है। लाउडस्पीकरों पर घूम-घूम कर जनहित में घोषणाओं को भी बहुत गरम दिनों में किया जाना चाहिए।

प्रश्न : यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहती है तो क्या लू की तीव्रता भविष्य में और बढ़ जाएगी ? शहरों द्वारा लू के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का क्या उपाय किए जाने चाहिए ?

उत्तर : हां, अध्ययन दर्शाते हैं कि भविष्य में लू की तीव्रता और आवृत्ति के बढ़ने की संभावना है।



शहरों को पौधा-रोपण के बड़े अभियान चलाने चाहिए और बागों को विकसित करना चाहिए क्योंकि वे हमें सूरज की रोशनी से बचाकर छाया प्रदान करते हैं। शिक्षण संस्थानों को अपने समय में परिवर्तन करना चाहिए और ये सुबह 07:00 बजे से 11:00 बजे तक खोले जाएं। इसी तरह बाजारों को तेज लू चलने के घंटों के दौरान बंद रखा जाना चाहिए।

नगर निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि तेज हवा चलने के घंटों के दौरान कोई बिजली कटौती न की जाए। श्रम नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए; काम करने का समय सुबह तथा शाम के घंटों तक सीमित किया जाए, सार्वजनिक स्थानों पर शीतल आश्रय केंद्र और साफ पीने के पानी के इंतजाम किए जाएं।

प्राधिकरणों को वायु प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

प्रश्न : कब, क्यों और कैसे नागपुर लू कार्य योजना को तैयार किया गया ?

उत्तर : नागपुर में हर गरमी के मौसम में कम-से-कम 30-50 दिनों तक भयंकर लू चला करती है। पिछले 10 सालों में, बुनियादी ढांचा तथा आबादी के अर्थों में शहर कई गुना बढ़ गया है, जिसके कारण पानी की कमी तथा जंगलों की कटाई का होना है। लू से बचने के लिए शहर को तैयार करने हेतु मई, 2015 में नागपुर लू कार्य योजना बनाई गई।

मई, 2016 में जलवायु परिवर्तन के लिए तैयारी पर महाराष्ट्र के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यशाला में, विशेषज्ञों ने लू और इसकी बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति के खिलाफ जंग लड़ने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया। 6 शहरों-नागपुर, चंद्रपुर, गोडया, अकोला, जलगांव और नांदेड-को अहमदाबाद लू कार्य योजना (एचएपी) की तरह ही अपनी लू कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए चुना गया और इस कार्यशाला में संबंधित ज्ञान हासिल किया गया। नागपुर निगम को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा गया।

इस योजना को एनडीएमए, भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान (आईआईपीएच), अहमदाबाद तथा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के समन्वय से तैयार किया गया।

प्रश्न : इस योजना से शहर को अपनी लू संबंधी तैयारी को बेहतर बनाने में कैसे मदद मिलेगी ?

उत्तर : इस योजना से अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूती, तैयारी के कार्यकलापों, गरमी के कारण होने वाली बीमारियों तथा मौतों की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के काम को बेहतर ढंग से करने में मदद मिली। इसने समुदाय तथा अधिकारी स्तर, दोनों पर समुदाय में जागरूकता बढ़ाने, तथा निवारक उपायों के व्यापक उपयोग में भी मदद की। इसने चिकित्सा व्यावसायिकों और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की गरमी से जुड़ी बीमारियों के निदान और उससे जुड़े मामलों में इलाज की क्षमता बढ़ाने का भी काम किया। इन सभी उपायों से मृत्यु दर में, पिछले वर्षों में लू से हुई मौतों की तुलना में, उल्लेखनीय कमी आई।

प्रश्न : क्या नागपुर निगम इस साल लू का सामना करने के लिए तैयार है ?

उत्तर : सभी हितधारकों की एक बैठक का पहले ही आयोजन किया जा चुका है और आगामी लू-मौसम 2018 के लिए कार्यकलापों की योजना बना ली गई है। •

क्या आप लू का सामना करने के लिए तैयार हैं ?

निम्नलिखित सावधानियां बरतें

- पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं—तब भी जबकि प्यास न लगी हो।
- ओरआरएस (ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन), घर में बने हुए पीने की मदें जैसे लस्सी, तौरानी (चावल का पानी), नींबू परनी, छाछ आदि ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न रहें।
- फोन, टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से स्थानीय मौसम की खबरों से जुड़े रहें।
- हल्के वजन के और हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहने।
- अपने सिर को किसी कपड़े, टोप (हेट) या छाते की सहायता से ढके।
- जानवरों को छायादार जगह के नीचे (शेड में) रखें और उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी दें।
- बच्चों और पशुओं को पार्क की गई गाड़ियों में न छोड़े क्योंकि वे इससे लू की चपेट में आ सकते हैं।